चीनी मिलों को बिना ब्याज के कर्ज देने की तैयारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : गन्ना मूल्य पर सियासत और

उत्तर प्रदेश में पेराई शुरू न करने पर अड़े चीनी मिलों को मनाने के लिए केंद्र सरकार ने बीच का रास्ता निकालने का फैसला किया है।

खाद्य मंत्रालय ने वित्तीय संकट का दावा कर रहे चीनी उद्योग को बैंकों से ब्याज रहित कर्ज दिलवाने का प्रस्ताव किया है। खाद्य सचिव सुधीर कुमार ने बताया कि मंत्रालय इस बारे में कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है। इसे जल्द ही कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। पिछले हफ्ते कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह के साथ चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों की हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। बैठक में उद्योग की ओर से यह मांग की गई थी सरकार उन्हें पैकेज के तौर पर कर्ज के ब्याज का भुगतान करे। इसी के आधार पर यह कदम उठाया जा रहा है। चीनी मिलों की माली हालत को देखते हुए बैंक उन्हें कर्ज देने से कतरा रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम उन्हें राहत दे सकता है। सुधीर कुमार ने बताया कि अगर बैंक उन्हें कर्ज देने के लिए आगे आते हैं तो इस पर लगने वाले ब्याज का भुगतान सरकार चीनी विकास फंड से करेगी। इस फंड में कसीब 1,200 करोड़ रुपये पड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर चीनी उद्योग पिछले दो चीनी सीजन के उत्पाद शुल्क के आधार पर दो साल के लिए 3,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेता है तो इस पर 380-400 करोड़ रुपये तक का ब्याज बनेगा। उद्योग का कहना है कि चीनी उत्पादन की लागत बढ़ने और घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में तेज गिरावट के चलते उन्हें वित्तीय मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते उनका गन्ना एरियर पिछले सीजन में बढ़कर 3,400 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। यूपी के मिलों द्वारा पेराई शुरू न करने पर कुमार ने कहा कि इसमें देरी से कुल चीनी उत्पादन पर असर पड़ेगा।

गन्ने पर सियासत

- खाद्य मंत्रालय कैबिनेट के समक्ष रखेगा प्रस्ताव
- चीनी विकास फंड से सरकार करेगी ब्याज भुगतान

जल्द सुलझाएं मामला : पीएम

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने

शरद पवार की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह से चीनी उद्योग की समस्याओं को जल्द सुलझाने को कहा है। समूह की पिछले हफ्ते उद्योग के प्रतिनिधियों से हुई बैठक में कुछ सिफारिशें की गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर इन सुझावों के जरिये उद्योग की दिक्कतों का हल निकालना संभव है तो इस दिशा में कदम बढ़ाएं जाएं। उद्योग की मुश्किलों को लेकर मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें इससे संबंधित ज्ञापन सौंपा।

यूपी में पेराई पर गतिरोध कायम

जाब्यू, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र शुरू करने पर बना गतिरोध मंगलवार को भी खत्म नहीं हो सका। अलबत्ता, सूबे के मुखिया अखिलेश यादव और चीनी मिल मालिकों के बीच कुछ अहम मसलों पर सहमति बनने से के आसार जरूर नजर आने लगे हैं। मिलों ने आश्वासन दिया है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देती है तो दिसंबर के पहले हफ्ते से पेराई शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री आवास पर रात पौने नौ बजे तक चली मिल मालिकों से वार्ता की अधिकृत जानकारी देने को दोनों पक्षों में से कोई तैयार नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने मिल मालिकों की समस्याओं को स्वीकारा जरूर लेकिन पेराई शुरू कराने पर जोर दिया। मिल मालिकों ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए अतिरिक्त रियायत दिलाने की मांग की। राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) 280-290 रुपये प्रति क्विंटल पर गन्ना खरीदने से मिलों ने फिर असमर्थता जताई। उनका कहना था कि 225 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा मूल्य देने की स्थिति में मिलें नहीं हैं।

एंट्री टैक्स और समिति कमीशन पर मांगी छूट : विशेष पैकेज मांग रहे मिल मालिकों ने प्रवेश कर व गन्ना समिति कमीशन से छूट की राज्य सरकार से मांग की। उनका कहना था कि इससे मिलों को राहत मिलेगी। मिलों की ओर से किराया कटौती में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव आया लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे खारिज कर दिया।

दैनिक जागरण
27/11/13